भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय परिषद बैठक
स्व. सूर्यभान वहाडने पाटिल परिसर
7–8 फरवरी, 2009
नागपुर

आर्थिक प्रस्ताव

कभी–कभी एक परिवार की एक पीढ़ी में एक ऐसा निकम्मा पुत्र पैदा हो जाता है जो अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और फिजुलखर्ची से परिवार की कठोर परिश्रम से अर्जित सम्पत्ति का सत्यानाश कर देता है और परिवार के भविष्य को तबाह कर देता है। भाजपा राष्ट्रीय परिषद का मानना है कि यूपीए सरकार ने उसी गुमराह पुत्र की तरह पिछले पांच वर्षों में व्यवहार किया है और एक पूर्णतः स्वस्थ अर्थव्यवस्था को लगभग तबाह कर दिया है। जब मई 2004 में डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने सत्ता संभाली थी तो देश के कई लोगों ने सोचा था कि उनके कुशल नेतृत्व में भारत के स्वर्णिम युग की शुरूआत हो पाएगी। पांच वर्षों के बाद उनका यह स्वप्न छिन्न–भिन्न हो गया है।

जब मई 2004 में यूपीए सरकार ने सत्ता संभाली तो उसे विरासत में एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई थी। जुलाई 2004 में, इस सरकार ने अपने प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण में कहा था कि ''लगता है कि विकास, मुद्रास्फीति और भुगतान–संतुलन के रूप में अर्थव्यवस्था तंदरूस्त हालत में है जो कुल मिलाकर ऐसा संयोग है, जिससे 'मेक्रो–इकानामिक' स्थिरता जारी रहने के साथ–साथ विकास को सुदृढ़ करने तथा गति को तेज करने की गुंजाइश बनी रहेगी।'' इसमें आगे लिखा गया था कि ''कृषि के अलावा उद्योग और सेवा क्षेत्रों में भी गतिशीलता बनी रहेगी, जिससे 2002–03 में इन दो सेक्टरों में जो जीडीपी विकास क्रमशः 6.4 प्रतिशत और 7.1 प्रतिशत की दर से हुआ था वह 2003–04 में बढ़कर क्रमशः 6.5 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत हो जाएगा। 2003–04 की दूसरी से तीसरी तिमाही के विकास में खनन और उत्खनन; बिजली, गैस और जलापूर्ति; व्यापार, होटल, परिवहन और संचार और वित्त पोषण, बीमा, अचल सम्पत्ति और कारोबारी सेवाओं में मोटे तौर पर विकास की तीव्र गति देखी गई।'' आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था ''मौलिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हैं और भुगतान संतुलन अत्यंत मजबूत हैं।'' चार वर्षों से अधिक समय तक यूपीए सरकार बिना किसी अपने प्रयास के एनडीए सरकार द्वारा विरासत में छोड़ी गई गति के आधार पर चलती रही। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है उसने इस विरासत को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। एनडीए शासन के आखिरी वर्ष यानी 2003–04 से लेकर 5 वर्षों तक 8 प्रतिशत से अधिक के विकास दर ने इस सरकार को ऐसा धुत कर दिया कि वह इसको अपनी सफलता मान कर और आत्मसंतुष्टि का मिथ्या चोला पहन कर इस विकास को आगे बढ़ाने में जरा भी अपना योगदान नहीं किया। इसके बजाए कि यूपीए सरकार और प्रयास करते हुए इस विकास दर को आगे बढ़ाती और भारत के विकास दर को दो–अंकीय बनाती, इस सरकार ने न केवल आर्थिक सुधार रोक दिए, बल्कि उसे उल्टी दिशा में ले जाने का काम किया और एनडीए सरकार ने राजमार्गों के विकास, नदियों को एक दूसरे से जोड़ने और पेंशन सुधार जैसे जो उपयोगी कदम उठाये थे, उसको जहां का तहां रोक दिया। अर्थव्यवस्था की बदइंतजामी के कारण बहुत सारे असंतुलन पैदा हो गए, जैसे बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा, बढ़ता हुआ चालू खाते का घाटा, बढ़ती मुद्रास्फीति और अंततः ध्वस्त होती अर्थव्यवस्था। इनमें से किसी का भी संबंध विश्व के हाल के वित्तीय संकट से नहीं है। ये सारी कठिनाईयां यूपीए सरकार की गलत नीतियों और उद्धत रवैये का परिणाम हैं। संकट गहराता चला गया और सरकार ने समय रहते आवश्यक उपाए नहीं किए। वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के नवीनतम मौद्रिक नीति विवरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा हैः ''2008–09 की प्रथम छमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर में साइक्लिकल धीमापन तथा बढ़ती मुद्रास्फीति का दौर चला।'' भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद भारतीय रिजर्व बैंक का सम्मान करते हुए भी कहना चाहेगी कि

यह तथाकथित 'धीमापन' वास्तव में 'मंदी' है और इसे साइक्लिकल भी कहना सही नहीं है, यह तो यूपीए सरकार की आर्थिक कुव्यवस्था का सीधा परिणाम है।

सच तो यह है कि एनडीए सरकार ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था छोड़ी थी जिसमें विकास के लिए पर्याप्त गति और कुशलता थी जिसके आधार पर अगले कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था का विकास दर निरंतर 8–9 प्रतिशत के स्तर पर बना रह सकता था। लेकिन वैश्विक वित्तीय अस्थिरता तथा यूपीए सरकार के गैर–जिम्मेदाराना खर्च नीति के कारण 2008 मुद्रा स्फीति की दर तेजी से बढ़ी और आरबीआई को मौद्रिक 'ब्रेक' लगाने की जरूरत पड़ी। फिर तो तुरन्त ही औद्योगिक उत्पादन, ऋणविस्तार, और बुनियादी ढांचों पर खर्च घटना शुरू होना ही था और ब्याज दरों को बढ़ना ही था। अतः जब 2008 के दूसरे भाग में भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जो पहले से ही धीमी पड़ चुकी थी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संकट की मार पड़ी तो संकट और गहराया। अब फिर से भारतीय अर्थव्यवस्था को 8–9 प्रतिशत के विकास दर पर लाने के लिए दुगुनी मेहनत करनी होगी क्योंकि इसके लिए एक ओर तो यूपीए सरकार की गलत नीतियों को ठीक करना होगा और दूसरी ओर विश्व की आर्थिक मंदी से निपटना होगा।

यूपीए सरकार की तथाकथित आर्थिक 'ड्रीम टीम' ने ऐसी गलत नीतियों पर चलने का काम क्यों किया? भाजपा राष्ट्रीय परिषद का मानना है कि यूपीए सरकार ने आर्थिक नीति का संचालन आर्थिक सिद्धांतों पर कम और राजनैतिक तथा अनैतिक सिद्धांतों पर अधिक किया है। इस सरकार का पहला सिद्धांत यह था कि किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहो। इस सरकार के तथाकथित महान सुधारकों को वामपंथियों को तुष्ट करने और सत्ता में बने रहने के लिए आर्थिक सुधारों को तिलांजलि देने में जरा भी हिचक नहीं हुई। पेंशन सुधारों से जहां एक ओर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता था वहीं दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी पेंशन का लाभ मिलत सकता था। सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार ने पेंशन सुधार के लिए अत्यधिक चिंता जताते हुए एक अध्यादेश भी जारी किया। फिर, वामपंथियों के दबाव में आकर उसने अगले चार वर्षों तक संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को भी दबाये रखने का काम किया। आज, वह चोरी छिपे वह करने की कोशिश कर रही है जो वह कानून बनाकर नहीं कर पायी।

इसी प्रकार, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित मंत्री ने इस काम में बेहद बदइन्तजामी की; लेकिन प्रधानमंत्री उन्हें अनुशासित नहीं कर पाए और उनके अनैतिक और भ्रष्ट व्यवहार पर रोक नहीं लगा पाए। बल्कि इसके विपरीत वह खुद ही उस मंत्री की कपटपूर्ण चालों के सहयोगी बन गए ताकि उनकी पार्टी का समर्थन सरकार को मिलता रहे। इसी प्रकार, जब स्वास्थ्य मंत्री ने आल इंण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज की स्वायत्तता और गुणवत्ता पर हमला बोला तो प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने रहे।

आर्थिक प्रबंधन में यूपीए सरकार का दूसरा सिद्धांत है वोट बैंक की राजनीति। इस सिद्धांत का सबसे अधिक प्रभाव देश की कृषि और देश के किसानों के ऊपर पड़ा। भाजपा राष्ट्रीय परिषद का मानना है कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने आज की कृषि आपदा के बीज उस समय बो दिए थे जब वे स्व. पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे। इस अवधि में कृषि में पूंजीगत निवेश बुरी तरह से घटा। ग्रामीण बुनियादी ढांचे की बुरी तरह उपेक्षा हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नजरअंदाज किया गया। कृषि विस्तार सेवाएं ठप्प पड़ गईं। भारत के किसानों को उनकी नियति पर छोड़ दिया गया।

एनडीए शासन के दौरान हमने इस नीति को किसान क्रेडिट कार्ड, वाटरशेड विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कोल्ड स्टोरेज और गोदामों के निर्माण, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, बेहतर फसल बीमा योजना तथा अंत में किसानों की आय बीमा योजना तथा खेती के ऋणों में ब्याज दरों में कमी लाकर बदलने का प्रयास किया।

यूपीए सरकार ने इनमें से बहुत सी योजनाओं के मात्र नाम बदल डाले और उन्हें अपनी योजना बनाने का दावा किया। 'भारत निर्माण' पहले से चली आ रही योजनाओं को एक साथ मिला देने के अलावा और कुछ नहीं है। यूपीए सरकार ने 2008–09 को समाप्त होने वाली 'चार वर्षीय बिजनेस प्लान' कहकर इन योजनओं में एक नया आयाम जोड़ने की कोशिश की, परन्तु वह इसके लक्ष्यों तक दूर–दूर तक नहीं पहुंच पाई। सुविख्यात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हमारी सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का ही बदला नाम है। इस प्रकार के अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं।

इस शासनकाल में किसानों की आत्महत्याएं आम बात हो गई हैं। चार वर्षों तक यूपीए सरकार का दिल किसानों के लिए नहीं पसीजा। लेकिन चुनाव सिर पर आते ही बिना सोचे विचारे उसने झटपट एक ऋण माफी योजना बना डाली। स्वाभाविक है कि ऋण माफी योजना का आकार बड़ा होने के बावजूद भी वह कृषि आपदा की चुनौतियों का सामना करने में विफल रहीं और किसानों की आत्महत्याएं जारी रहीं। इस सरकार ने एनडीए सरकार की उस शानदार योजना पर कुछ नहीं किया, जिससे किसानों को आय बीमा की सुविधा मिलती। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में अभी तक सारे किसानों को शामिल नहीं किया गया है, हर खेत की सिंचाई अभी तक सपना ही बनी हुई है। कृषि के लिए आवश्यक वस्तुऐं विशेष रूप से उर्वरक, खेत–पम्पों के लिए मिट्टी का तेल और कीटनाशक दवाईयां और महंगी हुई हैं और छोटे तथा सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर हैं। यदि यूपीए सरकार किसी एक मामले में सबसे ज्यादा असफल रही है तो वह है कृषि और किसानों के मामले में।

भारत सरकार के बजट का साम्प्रदायीकरण इस सरकार की एक और काली करतूत है जिसके पीछे एक मात्र उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति है। इसके बजाए कि पिछड़ापन, निर्धनता और अपवंचिता संसाधन बांटने के सिद्धांत हों, इस सरकार ने 'मजहब' को ही संसाधन उपलब्ध कराने का आधार मान लिया है। प्रधानमंत्री का यह कहना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, सेक्युलरिज्म पर सीधा प्रहार है।

इस सरकार का तीसरा सिद्धांत है– जैसे सम्भव हो वैसे पैसा बनाया जाए। यूपीए सरकार के शासनकाल में आर्थिक नीतियों और बड़ी योजनाओं को सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को दिया गया है। यह सबसे बड़ी अनैतिकता है। एनडीए ने विश्वस्तरीय 'सेज' को प्रोत्साहन देने वाली नीति बनाया था ताकि चीन के 'सेज' से मुकाबला किया जा सके। इसकी बजाए, यूपीए ने 'सेज' नीति को भ्रष्ट राजनीतिज्ञों के लिए एवं अचल सम्पत्ति को हथियाने का निरा साधन बना कर रख दिया है। बड़े–बड़े आधुनिक विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के नाम पर कोयला खानों को लगभग मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। टेलीकोम लाइसेंस में 'बोली' की धोखाधड़ी वाली प्रक्रिया को अपनाया गया है। और, अंत में 'सत्यम' घोटाले ने दुनिया भर के सामने भ्रष्ट कांग्रेसी राजनेताओं और फूहड कारोबारी परिवारों के बीच के नापाक सम्बंधों का पर्दाफाश कर दिया है। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद इस प्रस्ताव के माध्यम से देशवासियों से वादा करती है कि हम बैंकों, लेखा परिक्षी संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेश को और पूंजी बाजार के अन्य घटकों के व्यवहारों के बारे में एक सुपर सक्षम नियंत्रण संरचना खड़ी करेंगे जिससे सत्यम जैसे घोटालों की पुनरावृत्ति न हो पाए। टेलेकॉम स्पैक्ट्रम आवंटन के बारे में पूरे घटनाक्रम की नये सिरे से जांच कराने के बारे में भी यह राष्ट्रीय परिषद जनता से वादा करती है।

यूपीए सरकार ने जिस चौथे अनैतिक सिद्धांत को अपनाया है, वह है 'मेरे बाद प्रलय' अर्थात् 'After me the deluge'। आरबीआई और प्रधानमंत्री की इकानामिक एडवाइजरी कौंसिल (आर्थिक सलाहकार परिषद) दोनों ने अपनी नवीनतम रिपोर्टों में स्पष्ट संकेत दिये हैं कि इस वर्ष सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 8 प्रतिशत से अधिक होगा। हमारा अपना अनुमान है कि इस वर्ष भारत सरकार का घाटा जीडीपी के 10 प्रतिशत की सीमा को भी लांघ जाएगा। किन्तु इससे भी बड़े दुख की बात है कि पिछले वर्ष अपना बजट पेश करते हुए इस मुद्दे पर तत्कालीन वित्त मंत्री ने ईमानदारी का परिचय नहीं दिया। आज, 28 फरवरी 2008 को प्रस्तुत बजट 'सत्यम' के बही खातों की तरह चिथड़े–चिथड़े हुआ पड़ा है। इस सरकार ने बांड के रूप में बहुत बड़ी देनदारियों को आगे के वर्षों पर डाल दिया है। यहां तक कि छठे वेतन आयोग की बकाया राशियों की देनदारी और किसान ऋण माफी योजना को अगले दो–तीन वर्षों के लिए फैला दिया है। आधुनिक भारतीय आर्थिक इतिहास में बजट निर्माण का यह बेईमान हस्तकौशल बेमिसाल है। राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर इन चीजों को दुरूस्त करने में भावी सरकार को कई वर्ष लग जाएंगे।

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से उत्पन्न वित्तीय बोझ के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति बुरी तरह चरमरा गई है। भाजपा चाहती है कि केन्द्र सरकार इस बोझ का कुछ हिस्सा स्वयं वहन करे क्योंकि यह बोझ उसी के फैसलों के कारण पड़ा है। इसी तरह भारत सरकार की राजस्व वसूली में आई भारी कमी के कारण हुई राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति योजना अनुदान के माध्यम से की जाए।

इस सरकार द्वारा अपनाया गया पांचवा सिद्धांत यह है कि या तो आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों की उपेक्षा करो या संकट को और गहराने दो, चाहे वह ग्रामीण विपदा की बात हो, महंगाई की बात हो या विश्व में फैली वित्तीय मंदी हो। सच्चाई तो यह है कि वर्तमान मंदी इस सरकार की गलत नीतियों का सीधा परिणाम है, विशेष

रूप से जिस ढंग से इस सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने की कोशिश की। इस सरकार ने आरबीआई के साथ मिल कर तरलता को कसने के कई उपाए किए, वित्तीय संस्थानों को ब्याज दरें बढ़ाने पर मजबूर किया और ऐसे भी उपाए किए जिनसे क्रेडिट मिल ही ना पाए तथा इतना महंगा हो जाए कि लोग ऋण ले ही न पाएं। इस बात को देखते हुए कि भारत सरकार पहले ही बहुत बड़े राजकोषीय घाटे में चल रही थी और तरलता भी पहले से ही दबाव में थी, इन मौद्रिक उपायों से स्थिति और भी गंभीर हो गई। स्पष्ट है कि इसका प्रभाव, उपभोक्ता मांग और निवेश की मांग दोनों पर पड़ा। इन नीतियों का स्वाभाविक परिणाम यही हुआ कि अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई। यदि अब मुद्रास्फीति में कुछ गिरावट आई है तो यह सरकार की नीतियों के कारण नहीं है, बल्कि विश्वभर में छाई मंदी और वस्तुओं की कीमतों में भारी कमी के कारण है। परन्तु अब भी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें दो अंकों में ही हैं। 2008–09 की मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा में आरबीआई ने स्वीकार किया है कि हालांकि थोक मूल्य सूचकांक से नापा गया 'हैडलाइन इन्फ्लेशन' 2 अगस्त 2008 को 12.91 प्रतिशत की तुलना में आधे से अधिक गिर गया है, फिर भी प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में वस्तुतः बढ़ोतरी हुई है। दिसम्बर 2008 में सभी प्रकार के श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते दो अंकों में रहा। उर्वरक, एलपीजी सिलिण्डर और केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी कम रही। जिससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अकारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मुद्रास्फिती में तेजी के बावजूद कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी के ब्याज दर में जो एनडीए के कार्यकाल में 9.5 प्रतिशत था, घटाकर 8.5 प्रतिशत करने का निर्णय लेकर यूपीए सरकार ने श्रमिकों के साथ घोर अन्याय किया है।

इसी प्रकार, विश्वभर में छाए वित्तीय संकट के कारण पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने में भी यूपीए सरकार पूरी तरह विफल रही है। प्रथम, वह संकट का पहले से अनुमान ही नहीं लगा पाई। द्वितीय, वह यही राग अलापती रही कि 'हमारे फंडामेंटल बड़े मजबूत हैं।' तृतीय, वह इन तेजी से बदलती परिस्थितियों के साथ अपनी नीतियों का सामंजस्य नही बैठा सकी। चतुर्थ, उसकी सदा यही नीति रही कि आज थोड़ा कर लो कल थोड़ा कर लो। इससे विश्वास का संकट पैदा हो गया जिसके चलते स्टाक मार्केट ध्वस्त हो गया। एक बार फिर सर्वाधिक नुकसान छोटे निवेशकों को उठाना पड़ा। राष्ट्रीय परिषद को इस बात पर संतोष है कि भाजपा ने इस स्थिति का अनुमान लगा लिया था और बहुत पहले यानी कि 14 अक्तूबर 2008 को ही संकट से निपटने के लिए अपने सुझाव दे दिए थे। इसके बाद एक और दस्तावेज 30 अक्तूबर 2008 को जारी किया गया जिसमें पार्टी ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संकट से निपटने के लिए नाना प्रकार के उपाए बताए। प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 20 नवम्बर 2008 को संकट से निपटने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिए भारत के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय परिषद को इस बात पर खेद है कि सरकार ने पार्टी द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण लोगों को अकारण ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा की यह राष्ट्रीय परिषद वर्तमान वित्तीय संकट से लोगों को मुक्ति दिलाने हेतु वाजपेयी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे राष्ट्रीय महामार्ग योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नदियों को जोड़ने की योजना के सही क्रियान्वयन पर बल देने का वादा करती है। हमारा यह भी वादा है कि हम इस वित्तीय संकट के कारण रोजगार खोने वाले सभी के लिए समुचित सुरक्षा संरचना के लिए प्रयत्न करेंगे।

यूपीए सरकार का छठा सिद्धांत 'किसी बात की चिंता नहीं है' (could not care less attitude) का रहा है। आर्थिक मंदी जिस पर वैश्विक मंदी की मार भी अब पड़ रही है के चलते लाखों लोगों की आजीविका चली गई है। संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में भारी छंटनी हो रही है। इन लाचार श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा तंत्र नही है। कपड़ा उद्योग, कारपेट उद्योग, हीरे और आभूषण तथा शिल्पकलाओं का उद्योग, रियल स्टेट, आटोमोबाइल्स और हल्की इंजीनियरिंग उद्योग, छोटे और मझोले उद्योग, खनन, इस्पात, सीमेंट, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी पर करारे प्रहार हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में औद्योगिक विकास दर आधा रह गया है। सरकारी राजस्व लक्ष्य से बहुत दूर है। सेवा सेक्टर का विकास एक अंक में आ गया है। कृषि विकास अब भी मौसम पर निर्भर है और निश्चल है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने वर्ष 2008 को संकट का वर्ष कहा है। देश इस अभूतपूर्व वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है मगर यूपीए सरकार को इस महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व सम्भालने वाला कोई वित्त मंत्री अभी भी नहीं मिला है। प्रारंभ में तेा प्रधानमंत्री इस विभाग को सम्भाल रहे थे और अब उनकी हृदय शस्त्रक्रिया के बाद यह विभाग विदेश मंत्रीजी को दिया है जो पहले से बहुविध दायित्वों का भारी बोझ उठा रहे हैं। इस यूपीए सरकार को अपने पहले विदेशमंत्री को उनके अनैतिक व्यवहार के कारण जबकि गृहमंत्री को उनकी अकर्मण्यता के कारण हटाना पड़ा है। अब तो यह सरकार कोई पूर्णकालिक वित्तमंत्री ढूंढने में

भी विफल रही हैं। क्या इतनी अक्षम सरकार को पुनः सत्ता में लाना है ? भाजपा की यह राष्ट्रीय परिषद को यह कहते हुए अफसोस है कि अगर यूपीए सरकार सत्ता में बनी रहती है तो वर्ष 2009 और भी अधिक गहरे वित्तीय संकट का वर्ष साबित होगा और लाखों श्रमिकों को आजिविका से हाथ धोना पड़ेगा। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद इस तथ्य को खेद के साथ नोट करती है कि यदि संप्रग सरकार पुनः सत्ता में आती है तेा वर्ष 2009 में इससे भी बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा और कई लाख मजदूरों को अपनी आजीविका से हाथ धोना पड़ेगा।

मार्च 1998 में हमें एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था विरातस में मिली थी। वाजपेयी सरकार के छह वर्षों में, चुनौतियों के बावजूद, हमने पूरी तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखा, भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भण्डार को सुरक्षित क्षेत्र में बनाए रखा, देश को चिरस्थायी खाद्यान्न की कमी से मुक्ति दिलाई और बुनियादी ढांचे में भारी सुधार किए। इस अवधि में हमने कमी वाली अर्थव्यवस्था को 'बाहुल्य' की अर्थव्यवस्था में बदल डाला। किन्तु, वाजपेयी सरकार का सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने भारत को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाया। यह आर्थिक सुरक्षा फिर से संकट में है। यूपीए सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर फिर से भारत को कमजोर और दुर्बल बना दिया है।

भाजपा राष्ट्रीय परिषद सुशासन के अपने आर्थिक एजेण्डा का निर्माण निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर करने का संकल्प लेती हैः–

1. सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक ऐसे सन्तुलित तथा साम्यापूर्ण विकास मॉडल की स्थापना हो जिससे आर्थिक सुरक्षा, रोजगार की गारण्टी तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। प्रत्येक भारतीय को पर्याप्त पोषाहार, स्वास्थ्य, सेनीटेशन, जलापूर्ति का मौलिक अधिकार, शिक्षा और क्रेडिट प्राप्ति का अधिकार मिले। आधुनिक तकनीक तथा चुस्त–दुरूस्त कार्यान्वयन के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विकास और कल्याण की जितनी योजनायें हैं उनका सीधा लाभ लोगों को मिले और लीकेज नहीं हो। साम्यवादी प्रयोग विफल हो चुका है। अधुनातन संकट ने पूंजीवादी व्यवस्था की विफलता पर से पर्दा उठा दिया है 'भाजपा वादा करती है कि वह एक ऐसे अनोखे भारतीय विकास मॉडल को विकसित करेगी जो देश की विशिष्ट जरूरतों और साथ ही हमारे जैसे विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करेगी।

2. अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्व का सिद्धांत रोजगार सृजन का होगा। भारत में अगले पांच वर्षों में 15 करोड़ युवा वर्कफोर्स में शामिल होने वाले हैं जिनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। अतः हम सबसे अधिक बल श्रम प्रधान उद्योगों पर देंगे जैसे कि निर्माण उद्योग, कपड़ा उद्योग, मैनुफैक्चरिंग तथा बुनियादी ढांचा। भाजपा की राष्ट्रीय परिषद इस तथ्य को पुनः उजागर करना चाहती है कि एनडीए के कार्यकाल में हमने 6 करोड़ रोजगार अवसर मात्र पांच सालों में निर्माण किये थे।

3. पूरे भारत में कृषि को मजबूत बनाना और किसानों की आर्थिक आजीविका को बेहतर बनाना। इसके लिए किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान किए जाएंगे, फसल प्रबंधन के लिए सही निर्णय लिए जाएंगे, सर्वोत्तम कृषि टेक्नॉलाजी अपनाई जाएगी, पर्याप्त जलापूर्ति की जाएगी, सम्पत्ति के स्पष्ट अधिकार होंगे, आवश्यक ग्रामीण बुनियादी ढांचा खड़ा किया जाएगा जिससे किसान यथा सम्भव कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें और व्यापक आय बीमा योजना तैयार की जायेगी।

4. ग्रामीण बुनियादी ढांचे में हर गांव में बिजली की आपूर्ति तथा पक्की सड़क की व्यवस्था की जायेगी।

5. सभी भारतीयों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। इन दोनों क्षेत्रों का लाभ पब्लिक–प्राइवेट सांझेदारी से मिलेगा जिससे उत्कृष्टता में सुधार आएगा, स्पेशलाइज्ड सेवाएं प्रदान की जाएंगी और नई टेक्नालाजियों का विकास होगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, उच्च शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। अधिकाधिक अध्यापकों, प्रोफेसरों और स्वास्थ्य व्यावसायियों को प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। सही नीतियां अपनाकर भारत न केवल अपने देश में शिक्षाकर्मियों की बड़ी फौज तैयार कर सकता है बल्कि सारी दुनिया के लिए गुरू की भूमिका भी निभा सकता है।

6. इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्धस्तर पर तैयार करना। तेजी से विकास के लिए राजमार्गों, विद्युत संयंत्रों, परिवहन प्रणालियों, सिंचाई परियोजनाओं (जिसमें मध्यम और लघु योजनाएं शामिल हैं), रेलवे पटरियों, बंदरगाहों–

इन सभी की परम आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक है कि सही नियामक फ्रेमवर्क बनाया जाए, उचित तथा ईमानदारी से बोली लगाई जाय, सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था हो तथा इन सभी क्षेत्रों में से प्रत्येक से पर्याप्त निवेश–प्रतिलाभ प्राप्त हो सके।

7. अपने हाइड्रोकार्बन और नवीकरणीय स्रोतों का पूरा लाभ उठाते हुए भारत को उर्जा क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना। भारत की उर्जा आवश्यकताएं हमारे गैस और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडों के तेजी से विकास के लिए भी आवश्यक होगी। ग्रीन टेक्नालाजी को देश के विकास का प्रमुख माध्यम बनाया जायेगा और भारत के पास जो टेक्नालाजिकल संसाधन हैं उसके आधार पर वह इस उद्योग में विश्व नेता बन सकता है।

8. नगरों को पुनः सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक आधार पर निरन्तर प्रगति प्रदान करना। अगले 20 वर्षों में भारत की जनसंख्या का 45 प्रतिशत भाग नगरों में होगा, जिसके लिए प्रमुख नए नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। स्थानीय जवाबदेही को मजबूत बनाना होगा और नागरिक सेवाओं को तैयार करने के लिए समझदारी से पब्लिक–प्राइवेट सांझेदारी का चुनाव करना होगा। हमारे वर्तमान नगरों के साथ–साथ बहुत से नए नगर बसाने होंगे जैसा कि छत्तीसगढ़ और गुजरात में हुआ है।

9. वित्तीय सेक्टर में और सुधार करने होंगे परन्तु ये इस ढंग से किए जाएंगे जिनसे अनुचित घरेलू या बाहरी जोखिम नहीं उठाना पड़े। विशाल स्तर पर वित्तीय समावेश में सुधार करने की आवश्यकता है, प्राथमिक सेक्टर लैण्डिंग (विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर) के लक्ष्यों को पूरा करना आवश्यक है, प्राइवेट पूंजी का संग्रह और इनके लिए विश्व–स्तर विनियम तैयार करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, पूरी वित्तीय प्रणाली को पूंजीगत ढंग से सशक्त करना होगा ताकि विकास में मदद मिल सके।

10. रक्षा उत्पादन के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी सर्वोत्कृष्ट शोध और विकास की दक्षता तक पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए, सरकारी आवश्यकताओं और योजनाओं को यथासंभव पारदर्शी बनाना होगा। इसके बाद ही दीर्घ–कालीन अनुबंध किए जाएं ताकि प्राइवेट सेक्टर आवश्यक निवेश कर सके।

11. केन्द्रीय बिक्री कर को पूरी तरह हटाना और छोटे व्यापारियों के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही कर प्रणाली में सुधार लाना। कराधान प्रणाली में इन सुधारों में शामिल हैं–वैयक्तिक आयकर की छूट सीमा को मुद्रास्फीति की दर से जोड़ना, सरकार द्वारा इमदाद प्राप्त वस्तुओं को वैट से मुक्त रखना और कर की दर में आमतौर पर कमी करना।

12. महिलाओं में उद्यमशीलता के विकास को तथा बड़े पैमाने पर–विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में स्वयं–सहायता समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन देना।

भारतीय जनता पार्टी भारत को सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए वचनबद्ध है। हम शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों का जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम देश को गरीबी, बदहाली और लाचारी से मुक्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम 2020 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में ला कर खड़ा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भाजपा सभी भारतीयों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश बनाने के लिए कृतसंकल्प है।

****